

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

23/2017
13.02.2017

- 1-हेमा पुत्री कल्लो जाति कंजर निवासी सोप तहसील उनियारा जिला टोंक राज०
 - 2-सहुल पुत्र हेमा जाति कंजर निवासी सोप तहसील उनियारा जिला टोंक राज०
 - 3-जुवरान पुत्र हेमा जाति कंजर निवासी सोप तहसील उनियारा जिला टोंक राज०
- अपीलान्ट्स

वनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला-टोंक

-रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय
नायब तहसीलदार सोप दिनांक 10.11.2016 मिसल नम्बर 612/2016

- उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र जैन, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय परोकार

निर्णय

दिनांक 23.05.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपन निर्णय दिनांक 10.11.2016 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1983 रकबा 0.01 हे० किरग बाराणी-1 भूदान बोर्ड वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर मकान का निर्माण चालू कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानत हुए भूमि से वेदखल करने, 5000/रु पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय परोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को धारा 91 ले०२०एक्ट के प्रावधानों के तहत तीनों को पृथक-पृथक नोटिस नहीं दिये और पृथक-पृथक निर्णय पारित नहीं किया वलिके संयुक्त रूप से नोटिस देकर, इनकी अनुपस्थिति दर्ज करते हुए एक निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट्स के विरुद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने बावत कोई साक्ष्य नहीं है। अपीलान्ट्स द्वारा कोई नया निर्माण नहीं किया गया है। पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश की है। अपीलान्ट्स के उक्त भूमि पर वर्षों से मकान बने हुये हैं और इनके अलावा अन्य व्यक्तियों के भी मकान बने हुये हैं। अपीलान्ट्स गरीब, भूमिहीन, मजदूर, गैर-सोपा व्यक्ति



जिला कलेक्टर
टोंक

है, जिनके पास निवास करने का अन्य कोई मकान या स्थान नहीं है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्त के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट्स को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1983 रकबा 0.01 है 0 किस्म बारानी-1 भूदान बोर्ड वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर मकान का निर्माण चालू कर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार सोप द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम कर 90 दिवस की सिविल कारावास की दजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। तहसीलदार उनियारा के आदेश क्रमांक 7164 दिनांक 20.10.2016 की पालना में अतिक्रमी को भू.अ.निरीक्षक सोप द्वारा व पटवारी हल्का सोप द्वारा दिनांक 20.10.2016 द्वारा पाबंद करने के उपरान्त भी अपीलांट्स द्वारा मकान का निर्माण कार्य चालू कर लिया है। अपीलान्त भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय परोकार की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलांत द्वारा नोटिस लेने से इनकार करने पर दो गवाहों के सामने मकान पर चरपा किया गया है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्त द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1983 रकबा 0.01 है 0 किस्म बारानी-1 भूदान बोर्ड वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर मकान का निर्माण कार्य चालू कर रखा है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं फर्द मौका रिपोर्ट से सिद्ध है। तहसीलदार उनियारा के आदेश क्रमांक 7164 दिनांक 20.10.2016 की पालना में अतिक्रमी को भू.अ.निरीक्षक सोप एवं पटवारी हल्का सोप द्वारा दिनांक 20.10.2016 को पाबंद करने के उपरान्त भी अपीलांट्स द्वारा मकान का निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया है। अपीलान्त भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप का निर्णय दिनांक 10.11.2016 यथावत रखा जाता है। रथगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(निम्नरी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टीक